

आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
रविवार 18.01.2026
समय 07.20

मुख्य समाचार :-

- जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान से आम लोगों को मिल रहा अपनी समस्याओं का समाधान; 45 दिन के अभियान में अब तक 21 हजार से अधिक लोगों की समस्याओं का हुआ निराकरण।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा- विकास के साथ-साथ सामाजिक संतुलन और सांस्कृतिक संरक्षण सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता।
- तीर्थनगरी हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए पिछले दो माह से सफाई अभियान जारी।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से केंद्रीय राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय, डॉ. राज भूषण चौधरी ने शिष्टाचार भेंट की। पेयजल योजनाओं और जल संरक्षण से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई।

जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा "जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार" कार्यक्रम प्रदेश में जनसमस्याओं के त्वरित समाधान का माध्यम बन रहा है। इस अभियान ने 45 दिन पूरे कर लिये हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी 13 जिलों में कुल 383 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों में अब

तक 3 लाख 7 हजार से अधिक नागरिकों ने भाग लिया है। कार्यक्रम के तहत सरकार को कुल 31 हजार से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 21 हजार से ज्यादा शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। अभियान के अंतर्गत नागरिकों को विभिन्न प्रकार के 42 हजार से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

इन शिविरों के जरिए राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत अब तक 1 लाख 67 हजार से अधिक नागरिकों को लाभ पहुंचाया गया है। सरकार का कहना है कि "जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार" कार्यक्रम के माध्यम से शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ है और आम नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री संबोधन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार अपने सभी निर्णय दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखकर ले रही है, जिसका उद्देश्य विकास के साथ-साथ सामाजिक संतुलन और सांस्कृतिक संरक्षण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार संवाद और पारदर्शिता में विश्वास रखती है और हर निर्णय का तर्क जनता के सामने रखना उसकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री देहरादून में आयोजित एक निजी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने लैंड जिहाद, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे विषयों पर सरकार के सख्त रुख की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संरचना की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत अब तक 10 हजार एकड़

से अधिक भूमि को मुक्त कराया गया है। साथ ही जबरन या प्रलोभन से किए जाने वाले धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लागू किया गया है।
मुख्यमंत्री ने मदरसा बोर्ड को भंग करने के निर्णय पर कहा कि सरकार शिक्षा में समानता और पारदर्शिता चाहती है, ताकि सभी बच्चों को आधुनिक शिक्षा और मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि यह कदम शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

स्पष्टीकरण

रुद्रप्रयाग ज़िले में महर्षि अगस्त्यमुनि महाराज की पारंपरिक देवरा यात्रा के दौरान हुई घटना को लेकर जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मुनि महाराज की डोली पर मुकदमा दर्ज होने की खबरें पूरी तरह भ्रामक और असत्य हैं। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा है कि प्रशासन धार्मिक आस्था और परंपराओं का पूरा सम्मान करता है, लेकिन अराजकता, हिंसा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक रिपोर्ट—जिला प्रशासन के अनुसार यात्रा के दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा अव्यवस्था फैलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और राष्ट्रीय राजमार्ग 107 को बाधित करने की घटनाएं सामने आई थीं। इस दौरान क्रीड़ा भवन के मुख्य द्वार को क्षतिग्रस्त किया गया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई घंटे तक आवागमन बाधित रहा। प्रशासन ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए दोषी तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

जिलाधिकारी ने बताया कि कार्रवाई किसी धार्मिक परंपरा के विरुद्ध नहीं, बल्कि केवल हिंसा और अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ की गई है। प्रशासन ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर डोली पर मुकदमे की अफवाह फैलाने वालों के

खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल शुक्ला और उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग सोहन सिंह सैनी ने भी स्पष्ट किया कि डोली पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है।

चारधाम यात्रा तैयारी

प्रदेश सरकार ने आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों शुरू कर दी हैं। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय ने ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप में उच्च स्तरीय बैठक करते हुए, अधिकारियों को सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यात्रा मार्गों को दुरुस्त रखने, पार्किंग क्षमता बढ़ाने, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और हेली सेवाओं सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की अभी से तैयारी सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। गढ़वाल आयुक्त ने कहा कि इस वर्ष यात्रा को और अधिक सुगम व सरल बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे।

स्वच्छता

तीर्थनगरी हरिद्वार को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए चलाया जा रहा सफाई अभियान दो माह पूरे कर चुका है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में यह अभियान शहर से लेकर गांव और कस्बों तक लगातार चलाया जा रहा है, जिसका असर अब धरातल पर दिखाई देने लगा है।

जिलाधिकारी ने सफाई अभियान को और तेज करने के उद्देश्य से 31 जनवरी तक महा स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जिला स्तरीय अधिकारियों का विभागवार रोस्टर भी जारी किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे दी गई जिम्मेदारियों का संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करें, ताकि जिले को साफ और स्वच्छ बनाया जा सके।

जिला प्रशासन ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी करें, ताकि हरिद्वार को साफ और स्वच्छ जिले के रूप में विकसित किया जा सके।

शिष्टाचार भेंट

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय, डॉ. राज भूषण चौधरी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य और केंद्र के बीच जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल योजनाओं, सिंचाई, स्वच्छ जल उपलब्धता और जल संरक्षण से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों, जल स्रोतों की संवेदनशीलता और सतत जल प्रबंधन की आवश्यकता पर बात रखी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय राज्य मंत्री को बताया कि राज्य सरकार, केंद्र के सहयोग से पेयजल आपूर्ति, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में जल स्रोतों के पुनर्जीवन और परंपरागत जल संरचनाओं के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. राज भूषण चौधरी ने उत्तराखंड में जल शक्ति मंत्रालय की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की और कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सहयोग प्रदान कर रही है। बैठक में भविष्य की जल परियोजनाओं, केंद्र-राज्य समन्वय और जल संसाधनों के सतत उपयोग पर भी विचार-विमर्श हुआ।

प्रशासनिक फेरबदल

प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 18, प्रांतीय सिविल सेवा के 11 तथा एक वित्त सेवा अधिकारी की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2001 बैच के अधिकारी आर. मीनाक्षी सुन्दरम से प्रमुख सचिव आवास, आयुक्त आवास तथा मुख्य प्रशासक उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण का प्रभार हटाया गया है। वहीं सचिव शैलेश बगौली से पेयजल विभाग का दायित्व वापस लिया गया है।

सचिन कुर्वे को सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा आयुक्त स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में भी महत्वपूर्ण अदला-बदली की गई है, जिनमें सहकारिता, आयुष, खाद्य, नियोजन, सैनिक कल्याण, राज्य सम्पत्ति, आपदा प्रबंधन और सचिवालय प्रशासन जैसे विभाग शामिल हैं।

सभी स्थानांतरित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने वर्तमान पदभार से कार्यमुक्त होकर तत्काल नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें।

और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर...

उत्तराखण्ड को स्टार्टअप में लीडर का दर्जा- हिन्दुस्तान समाचार पत्र इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है, केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में उत्तराखण्ड को दिया लीडर का दर्जा, सीएम धामी बोलो-राज्य में स्टार्टअप

नीति के जरिए नवाचार, निवेश प्रोत्साहन और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में कामयाब रहा...

बदरी-केदार समेत चारों धामों में मोबाइल ले जाने पर रोक-अमर उजाला की सुर्खी है। समाचार पत्र खबर में लिखता है- गढवाल आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुआ फैसला।

त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या का मुख्य आरोपी के खिलाफ वारंट जारी, अब नेपाल दूतावास करेगा हवाले- दैनिक जागरण इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है- बीएनएसएस की धारा 110 बनेगी देहरादून पुलिस का कानूनी हथियार।

बाहरी राज्यों से उत्तराखंड वाले वाहन चालकों को रखने के होंगे कागजात दुरुस्त, दस्तावेज ना होने पर कटेगा चालान- अमर उजाला की खबर- परिवहन विभाग कल से लागू करेगा ई-डिटेक्शन प्रणाली, सात टोल प्लाजा पर होगी ई-निगरानी।
